अधिप्रमाणित

राजस्थान सरकार
(राजकीय उपक्रम विभाग)
प्रगति विवरण वर्ष 2021–22

राजकीय उपक्रम विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में निम्न इकाईयॉ आती हैं :–

1) प्रबंधक, राजकीय लवण स्रोत,डीडवाना।
2) राजकीय उपक्रम ब्यूरो, जयपुर

1. राजकीय लवण स्रोत

(क) डीडवाना

नागौर जिले में स्थित डीडवाना के 1900 एकड़ में फैला हुआ यह स्रोत 1960 में केन्द्रीय लवण विभाग से उद्योग विभाग राजस्थान सरकार ने प्राप्त किया था। बाद में वर्ष 1964 में उद्योग विभाग से राजकीय उपक्रम विभाग को हस्तान्तरित हुआ था।

राजकीय लवण श्रोत, डीडवाना का आंशिक निजीकरण राज्य सरकार के आदेश दिनांक 27 जनवरी, 2000 के द्वारा किया गया था। प्रति क्यारे रायल्टी की नवीन दरें 10.10.2008 को निर्धारित की गई तथा क्रूड व्यवसाय का निजीकरण भी दिनांक 10.10.2008 से कर दिया गया। क्रूड सोडियम सल्फेट के निजीकरण की रायल्टी दरें आदेश दिनांक 03.05.2018 द्वारा शून्य कर दी गई है, अतः डीडवाना स्थित विभाग की वाणिज्यिक गतिविधियां बन्द हो गई। रॉयल्टी एवं प्लेटफार्म चार्ज के रूप में प्रति वर्ष राजस्व वसूली का कार्य यह विभाग करता है।

ख) पचपदरा

बाड़मेर जिले की बालोतरा तहसील स्थित पचपदरा के 32 वर्ग मील क्षेत्र में फैले लवण क्षेत्र को 1960 में उद्योग विभाग राजस्थान सरकार ने केन्द्रीय लवण विभाग से प्राप्त किया था और 1964 में इसका हस्तान्तरण राजकीय उपक्रम विभाग को प्राप्त हुआ। इस लवण क्षेत्र का निजीकरण अगस्त, 1992 में कर दिया गया था एवं रॉयल्टी का निर्धारण मात्र एक रूपया प्रति मै.टन रखा गया था। वर्ष 2002 में 10 वर्ष की निजीकरण की अवधि पूर्ण होने पर रॉयल्टी की दर बढ़ाकर पांच रूपया प्रति मै.टन कर

शासन उप सचिव
राजकीय उपक्रम विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर

(शकुन्तला रावत)
मंत्री
उद्योग, राजकीय उपक्रम
एवं देवस्थान विभाग

दी गई। मंत्रीमंडल आज्ञा संख्या 17/2007 दिनांक 19.1.2007 द्वारा निजीकरण की अवधि 10 वर्ष बढाये जाने एवं राजस्व वसूली राजस्व विभाग के माध्यम से करनें का निर्णय लिया गया है एवं रॉयल्टी की वसूली भी 500/– रूपये प्रति खान प्रति वर्ष करनें का निर्णय लिया गया। मंत्रीमण्डल आज्ञा 176/2018 दिनांक 01.09.2018 के अनुसार भी निजीकरण की अवधि 10 वर्ष बढ़ाने एवं रॉयल्टी की वसूली 500/– रूपये प्रति वर्ष प्रति खान करने का निर्णय यथावत रखा गया है।

गत पाँच वर्षों में राजस्व आय का विवरण निम्नानुसार है।

वर्ष	प्राप्त आय (रू.लाखों में)
2017–18	3.64
2018–19	7.53
2019–20	0.90
2020–21	3.12
2021–22 (दिसम्बर, 2021)	0.27

डीडवाना व पचपदरा लवण स्त्रोत का कार्य मंत्रीमण्डल सचिवालय की अधिसूचना दिनांक 21.08.2020 के द्वारा उद्योग (ग्रुप–1) विभाग को हस्तान्तरित कर दिया गया है।

2. राजकीय उपक्रम ब्यूरो, जयपुर

(अ) गठन

राजकीय उपक्रम ब्यूरो का गठन सितम्बर, 1984 में किया गया था। गठन के समय ब्यूरो के अधिकार क्षेत्र में 42 राजकीय उपक्रम सम्मिलित किये गये थे। सहकारी क्षेत्र के उपक्रमों को ब्यूरो की परिधि से अलग किये जाने/कुछ उपक्रमों का निजीकरण किये जाने, कुछ नये उपक्रमों को शामिल किये जाने, राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के स्थान पर पांच नई विद्युत कम्पनियों के गठन तथा राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम के राजस्थान राज्य खान एवं खनिज निगम में विलय, राज. इलेक्ट्रोनिक्स लि., राजकीय लवण स्त्रोत डीडवाना एवं राजस्थान स्टेट केमिकल्स डीडवाना को राजकीय उपक्रम ब्यूरो के अधिकार क्षेत्र से विलोपित करने के पश्चात वर्तमान में कुल 34 उपक्रम ब्यूरो के अधिकार क्षेत्र में कार्यरत है। सूची परिशिष्ठ 'अ' पर संलग्न है।

शासन उप सचिव
राजकीय उपक्रम विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर

(ब) सूचना संग्रहण एवं प्रकाशन

राजकीय उपक्रम ब्यूरो द्वारा राजकीय उपक्रमों के कार्य परिणामों को दर्शाने हेतु एक "पब्लिक एन्टरप्राईजेज प्रोफाइल" का प्रकाशन किया जाता है। वर्ष 2019–20 की प्रोफाइल का प्रकाशन किया जा चुका है एवं वर्ष 2020–21 की प्रोफाइल का प्रकाशन अन्तिम चरण में है।

(स) मार्गदर्शक आदेश एवं परिपत्र

ब्यूरो द्वारा राजकीय उपक्रमों में कार्यरत कर्मचारियों के सामान्य हितों के मामलों में विभिन्न राजकीय उपक्रमों के बीच एकरूपता लाने हेतु सेवा संबंधी विभिन्न प्रकरणों पर दिशा–निर्देश/परिपत्र जारी किये जाते हैं। इनमें राजकीय उपक्रमों के कर्मचारियों के वेतन–भत्तों एवं प्रदत्त अन्य सुविधाओं के संबंध में दिशा–निर्देश सम्मिलित हैं। बन्द किये जाने वाले उपक्रमों एवं अन्य उपक्रमों के अधिशेष कर्मचारियों को अन्य उपक्रमों में समायोजित करने एवं "स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति" हेतु एसआरएफ से ऋण उपलब्ध करवाने का लाभ दिया जा रहा है। बन्द होने वाले सार्वजनिक उपक्रमों के अधिशेष कर्मचारियों को सेवामुक्ति परिलाभों के प्रति आर्थिक दायित्वों के निर्वहन के लिए सार्वजनिक उपक्रमों को सहायता प्रदान करने हेतु एक "राज्य नवीनीकरण कोष" (स्टेट रिन्यूवल फण्ड) भी वर्ष 1995–96 में स्थापित किया गया है। इस फण्ड में जनवरी, 2022 तक 11.134 करोड़ रूपये की राशि राज्य सरकार के अंशदान के रूप में हस्तान्तरित की गई तथा जनवरी, 2022 तक विभिन्न राजकीय उपक्रमों से अंशदान के रूप में राशि रुपये 29.95 करोड़ रूपये प्राप्त हुए हैं। अब तक विभिन्न राजकीय उपक्रमों को दिये गये ऋण, वसूली एवं बकाया की स्थिति निम्नानुसार है :–

S.No.	PSUs	Loan Disbursed	Loan Recovered	Loan Balance	No. of Emp. Benifited
1	RSMDC	845.00	845.00		750
2	RSHDC-	442.65	442.65		137
3	RSAIC	200.00	0.00	200.00	325
4	RIICO	20.00	20.00		
5	RSHC	105.00	10.00	95.00	60
6	RSIC	733.44	166.66	566.78	134
7	RTDC-I	186.97	186.97	-	83
8	RTDC-II	1665.00	-	1665.00	225
9	RSHDC-II	250.00	-	250.00	27
10	RSHDC-III	50.00	-	50.00	-
	TOTAL	**4498.06**	**1671.28**	**2826.78**	**1741**

शासन उप सचिव
राजकीय उपक्रम विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के परिलाभ प्राप्त नहीं करने वाले अधिशेष कर्मचारियों को औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत सेवामुक्ति के उपरान्त् उन्हें राजकीय विभागों में रिक्त पदों के विरूद्ध अनुबन्ध पर रखने का निर्णय भी लिया गया है। इस हेतु कार्मिक विभाग द्वारा दिनांक 24.12.1994 को परिपत्र जारी किया हुआ है।

(द) <u>विभिन्न राजकीय उपक्रमों के 47 मृतक आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्तियां :–</u>

राजकीय उपक्रम ब्यूरो के नियन्त्रण में आने वाले राजकीय उपक्रमों के मृतक कार्मिकों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्तियां प्रदान करने के उद्देश्य से ब्यूरो ने पत्रांक 561–596 दिनांक 14.07.2010 एवं 02.05.2012 से निर्देश जारी किये।

इन निर्देशों के क्रम में अब तक जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. में 16, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम में 7, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में 1, राजस्थान राज्य बीज निगम जयपुर में 16, रीको में 3 एवं राजस्थान लघु उद्योग निगम में 4 प्रकरणों में नियुक्तियां प्रदान कर दी गयी हैं।

शासन उप सचिव
राजकीय उपक्रम विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर

TABLE - 1

THE BUDGET (Other than Scheme) ESTIMATE FOR 2021-22

(Rs. in lacs)

S.No.	Head of Account	Budget Estimate 2021-22	
Demand No.40			
	2852- Industries		
	80- General		
	001- Direction & Administration		
	(02) State Enterprises Department	42.97	
	(09) State Enterprises Department Bureau	75.12	
	08- Consumer Industries		
	600-Others		
	(01) - Salt Trading Scheme		
	Voted	20.97	
	Charged	0.01	
	Grand Total : Voted		**139.06**
	Charged		**0.01**

TABLE – 2

THE BUDGET (Schemes) ESTIMATE FOR 2021-22

(Rs. in lacs)

S.No.	Name of the Scheme	Outlay
1.	State Renewal Fund	25.50
2.	Capital outlay on Petroleum	155.00
	ToTal	180.50

शासन उप सचिव
राजकीय उपक्रम विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर

TABLE - 3

THE STATEMENT SHOWING THE REVENUE AND EXPENDITURE OF THE STATE ENTERPRISES DEPAERTMENT FOR 2017-18 To 2021-2022

(Rs. in lacs)

Particular	Years				
	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22 (up to 12/2021)
Revenue:					
(i) Salt Trading Scheme	3.64	7.53	0.90	3.12	0.27
Total	3.64	7.53	0.90	3.12	0.27
Expenditure:					
(i) State Enterprises	45.42	42.60	34.79	36.31	30.29
(ii) Bureau of Public Enterprises	48.53	61.71	56.90	66.12	55.09
(iii) Salt Trading Scheme	15.77	15.36	9.50	17.28	17.44
Total	113.36	119.67	101.19	119.71	102.82

शासन उप सचिव
राजकीय उपक्रम विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर

विभागीय संगठनात्मक ढाँचा
प्रशासनिक विभाग – शासन सचिव (राजकीय उपक्रम विभाग)

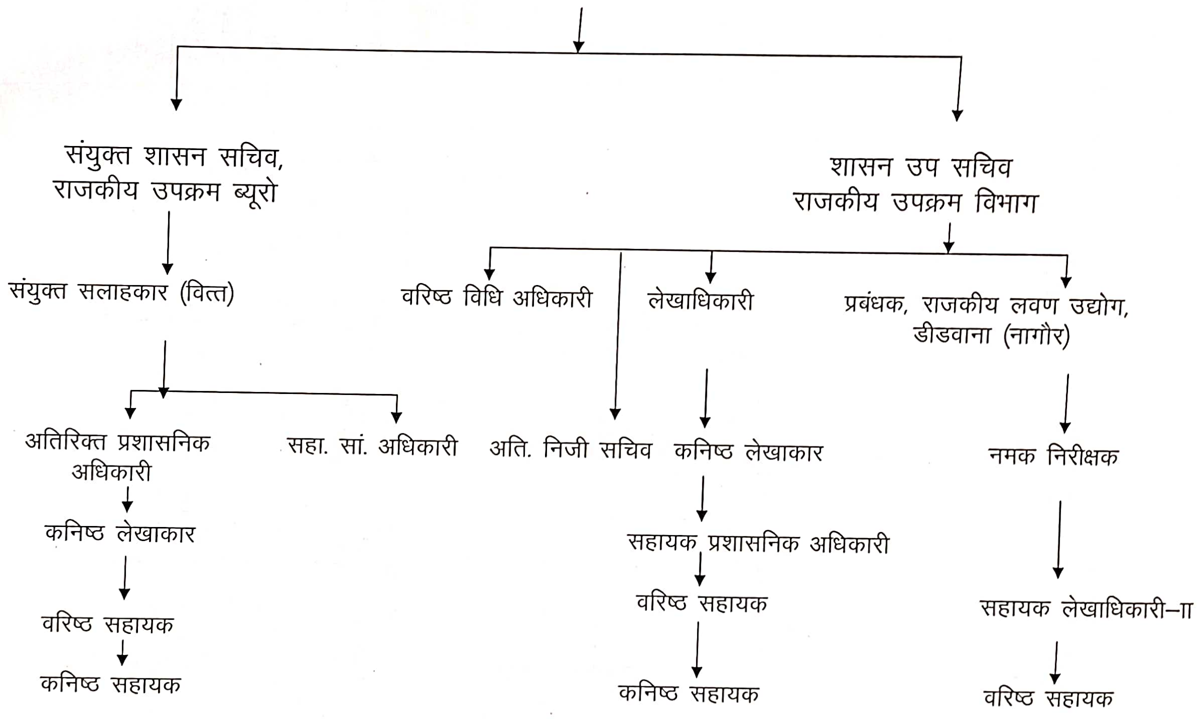

शासन उप सचिव
राजकीय उपक्रम विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर

Details of Posts

Budget Head : 2852-08-600-(01)-[00]

Post Type : Regular

S.No.	Designation Name	Grade Pay	Level in 7th pay matrix	Sanctioned Post	Vacant Post	Remarks
1	प्रबंधक	5400	14	1	1	S.D.M.- ADDL. Charge
2	निरीक्षक	3600	10	1	1	
3	सहायक लेखाधिकारी–II	4200	11	1	0	
4	वरिष्ठ सहायक	2800	8	1	0	
5	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	1700	1	2	1	
Total				6	3	

Budget Head : 2852-80-001-(02)-[00]

Post Type : Regular

S.No.	Designation Name	Grade Pay	Level in 7th pay matrix	Sanctioned Post	Vacant Post	Remarks
1	वरिष्ठ विधि अधिकारी	4800	12	1	1	
2	अतिरिक्त निजी सचिव	4800	12	1	1	
3	लेखाधिकारी	5400	14	1	0	
4	कनिष्ठ लेखाकार	3600	10	1	0	
5	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	3600	10	1	0	
6	वरिष्ठ सहायक	2800	8	1	0	
7	कनिष्ठ सहायक	2400	5	1	0	
8	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	1700	1	2	1	समेकित पारिश्रमिक पर एक कार्यरत
Total				9	3	

Budget Head : 2852-80-001-(09)-[00]

Post Type : Regular

S.No.	Designation Name	Grade Pay	Level in 7th pay matrix	Sanctioned Post	Vacant Post	Remarks
1	संयुक्त सलाहकार वित्त	7600	19	1	0	
2	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	4200	11	1	0	
3	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी	4200	11	1	1	RFC से विपरित प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत
4	कनिष्ठ लेखाकार	3600	10	1	0	
5	वरिष्ठ सहायक	2800	8	1	0	
6	कनिष्ठ सहायक	2400	5	1	0	
7	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	1700	1	2	1	समेकित पारिश्रमिक पर एक कार्यरत
Total				8	2	

शासन उप सचिव
राजकीय उपक्रम विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर

परिशिष्ट -'अ'

राजकीय उपक्रम ब्यूरो के क्षैत्राधिकार में आने वाले उपक्रमों की सूची

क्र. सं0	
	उपक्रम के नाम एवं विभाग
	वित्त आबकारी विभाग
1	राजस्थान राज्य ब्रेवरेज निगम लिमिटेड
2	राजस्थान राज्य गंगानगर शूगर मिल्स लि.
	स्थानीय स्वायत्त शासन विभाग
3	जयपुर शहरी परिवहन सेवा लिमिटेड
	खान एवं पैट्रोलियम विभाग
4	राजस्थान राज्य खान एवं खनिज निगम लि.,
5	बाडमेर लिग्नाईट खनन कम्पनी लिमिटेड
6	राजस्थान राज्य गैस लि.,
	ऊर्जा विभाग
7	राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लि.
8	जयपुर विद्युत वितरण निगम लि., जयपुर।
9	जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि., जोधपुर।
10	अजमेर विद्युत वितरण निगम लि., अजमेर।
11	राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि.
12	गिरल लिगनाइट पावर लिमिटेड
13	राजस्थान सोलर पार्क डवलपमेन्ट कम्पनी लि.
14	राजस्थान राज्य अक्षय ऊर्जा निगम
	वित्त विभाग
15	राजस्थान राज्य पावर फायनेन्स एण्ड फायनेशियल सर्विसेज कॉरपोरेशन लि
	सैनिक कल्याण विभाग
16	राजस्थान भूतपूर्व सैनिक निगम लिमिटेड
	सूचना प्रौघोगिकी एवं संचार विभाग
17	राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड
	चिकित्सा, स्वाथ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
18	राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉपेरेशन लि.
	खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले
19	राजस्थान राज्य खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम लि.
	पर्यटन विभाग
20	राजस्थान राज्य पर्यटन विकास निगम
21	राज. राज्य होटल्स निगम, जयपुर।
	उद्योग विभाग
22	राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट एण्ड इनवेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (रीको)
23	राजस्थान राज्य हाथकरघा विकास निगम
24	राजस्थान वित्त निगम
25	राजस्थान लघु उद्योग निगम
	कृषि विभाग
26	राजस्थान स्टेट बीज निगम
27	राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम लि.
28	राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम
29	राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड
	सिंचित क्षेत्र विकास विभाग
30	राजस्थान भूमि विकास निगम
	सार्वजनिक निर्माण विभाग
31	राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लि.
	परिवहन विभाग
32	राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम
	नगरीय विकास विभाग
33	राजस्थान आवासन मण्डल
	जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग
34	राजस्थान जल विकास निगम लि.

शासन उप सचिव
राजकीय उपक्रम विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर